मलेरिया विभाग के निगरानी निरीक्षक के प्रति किया गया अन्याय

1895. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बहु-उद्देश्यीय योजना को क्रियान्वित करते समय मलेरिया विभाग के निगरानी निरीक्षक संवर्ग को 135-190 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारियों के बराबर माना है तबकि उनका वेतनमान 195-330 रुपये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहु-उद्देश्यीय योजना के लिये सुपरवाइजरों के पद बनाने के संबंध में राज्य स्तर पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है और इन पदों के बनाये जाने का कार्य जिला अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ये असमानताएं दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर): (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना के एक अंग के रूप में, मलेरिया निगरानी निरीक्षक की कार्यवेक्षण पाठयक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । उन्हें 135-195 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारियों के बराबर नहीं माना गया है जिन्हें कार्यकर्ता पाठयक्रम में प्रशिक्षित किया पाठयक्रम में प्रशिक्षित किया गया है ।

(ख) जी नहीं, बहु-उद्देश्यीय योजना के लिए सुपरवाइजरों के पद बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Non Deposit of PF by Tea Estates in West Bengal

1896. SHRI SUBODH SEN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a number of Tea Estates have failed to deposit provident fund with the appropriate authority in the State of West Bengal; and

(b) if so, the names of the defaulting estates and the amount involved?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION AND LABOUR (SHRI J. B. PATNAIK): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Demilitarization of Indian Ocean

1897. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the Nations who are in favour of demilitarization of Indian Ocean;

(b) whether this region has become the cockpit of confrontation between U.S.A. and U.S.S.R.;

(c) if so, details thereof; and

(d) what is the reaction of the Government in regard thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) A majority of countries support the UN Resolution calling for the Establishment of a Zone of Peace in the Indian Ocean. A list of countries which had voted in favour of UN General Assembly Resolutions No. 34/80 A&B in December, 1979, is enclosed. These Resolutions called for the implementation of the Peace Zone Resolution, first adopted in December, 1971.

(b) It is a matter of regret that despite our earnest desire to see the Indian Ocean become a Zone of Peace, there has been a continuing escalation in the military presence of the Super Powers in this area.

(c) and (d). Consistent with our policy, we cannot but be concerned at any escalation in foreign military presence in this area. Any enhancement of the military presence of the two Super Powers will only add to the existing tension in this area.